संपादकीय

मुर्मू की उम्मीदवारी में समता का मर्म

यह सुखद ही है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिये पहली बार आदिवासी महिला को सत्तारूढ़ दल द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। यदि कुछ असामान्य न हो तो वोटों के गणित के हिसाब से उनका राष्ट्रपति बनना तय है। निस्संदेह, ऐसे फैसलों के राजनीतिक निहितार्थ भी होते हैं लेकिन सदियों से वंचित रहे आदिवासी समाज को ऐसा प्रतिनिधित्व देना सराहनीय है। राजग गठबंधन के इस कदम से जहां देश में सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता का संदेश गया है वहीं विपक्ष के साझा उम्मीदवार का दावा भी कमजोर हुआ है। विपक्ष ने जैसे शरद पवार, फारूख अब्दुल्ला व गोपाल कृष्ण गांधी को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की कोशिश की, उससे साफ लगता है कि विपक्षी एकता कमजोर है और नाम के चयन को लेकर गंभीर प्रयास नहीं किये। कालांतर पूर्व प्रशासक व राजनेता यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बनी है लेकिन उनके जीत के समीकरण निस्संदेह कमजोर हैं। राजग की सधी चाल का यह नतीजा है कि मजबूत विपक्ष का हिस्सा रहने वाले ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राजग प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को न केवल समर्थन दिया है बल्कि ओडिशा के आदिवासी समाज से आने वाली इस प्रत्याशी को सभी दलों से राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर वोट देने की अपील भी की है। ताकि पहली बार ओडिशा की कोई बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हो सके। ऐसा ही दबाव देश के अन्य आदिवासी बहुल राज्यों मसलन झारखंड के राजनीतिक दलों पर भी होगा। निस्संदेह, ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में यदि मुर्मू अगले माह होने वाले चुनाव में जीतती हैं तो वह आदिवासी समुदाय, ओडिशा मूल की पहली प्रतिनिधि और देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर आने वाली दूसरी महिला बन जायेंगी। वाकई मुर्मू उन लोगों के लिये प्रेरणास्रोत बनेंगी जिन्होंने गरीबी के बीच बेहद कठिनाइयों का सामना किया है। इस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट के जरिये किया है।हालांकि, के.आर. नारायणन, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद वे तीसरी दलित राष्ट्रपति होंगी, लेकिन आदिवासी समाज का वह पहला प्रतिनिधि चेहरा होंगी। वह समाज जिसने विकास से विस्थापन की बड़ी कीमत चुकाई है। ऐसा नहीं है कि उनके उत्थान के लिये देश में कानून नहीं बने, लेकिन वास्तविक धरातल पर उन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिल सका। देश में आदिवासी समाज लंबे समय से उपेक्षित रहा है। वैसे भी द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष हर भारतीय के लिये प्रेरणास्पद है। एक स्त्री के जीवन की ऐसी त्रासदी कि उसने पति व दो पुत्रों को खोने के बाद हिम्मत नहीं हारी और पढ़ -लिखकर अपनी मंजिल हासिल की। एक सामान्य सरकारी कर्मचारी, स्कूल शिक्षिका के रूप में जीविका जुटाने के बाद एक पार्षद के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। फिर दो बार विधायक बनीं और बीजद-भाजपा की सरकार में मंत्री बनीं। उनके राजनीतिक जीवन में झारखंड के राज्यपाल की पारी उल्लेखनीय रही है। लेकिन उसके बावजूद उनका जीवन सहज-सरल ही रहा है। हाल के दिनों में वायरल हुए वीडियो व अखबारों में सुर्खी बनी उनकी एक फोटो में वे एक मंदिर में सफाई करती नजर आ रही हैं। निस्संदेह उनकी सफलता से आदिवासी व महिला समाज को संबल मिलेगा। लेकिन जरूरी है कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक महत्व का विषय ही न बन कर रह जाये। जमीनी हकीकत में भी सामाजिक न्याय की कवायद सिरे चढ़े। तभी यह देश के जनजाति समुदाय व भारतीय लोकतंत्र के लिये सार्थक सिद्ध होगा। जरूरी है कि देश के वंचित समुदाय को लेकर राजनीतिक चेतना का भी विकास हो, जिससे सामाजिक न्याय को हकीकत बनाया जा सके। इसके लिये जरूरी है कि इस वर्ग को लेकर सामाजिक सोच में भी बदलाव आये। लेकिन एक बात तो तय है कि उच्च संवैधानिक पदों पर समाज से अलग-थलग रहने वाले वर्ग को यदि प्रतिनिधित्व मिलता है तो बदलाव की नई राहें खुलती हैं। जरूरत इस बात की है कि देश का राजनीतिक नेतृत्व इसके प्रति संवेदनशील रहे। राजग ने मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर यही संदेश देने की कोशिश भी की है।

मालदीव में सरकार विरोधी चक्रव्यूह में भारत

विश्लेषण

पुष्परंजन

पीपीएम के नेता अब्दुल्ला यामीन को लगा कि सत्ता में दोबारा से आना है, तो भारत की हर शै का विरोध करो। योग को हिंदू धर्म से जोड़कर मालदीव में राजनीतिक उन्माद पैदा करना भी इसी कवायद का हिस्सा रहा है। योग शिक्षिका सविता हरीश बताती हैं कि हमने यह सब देखकर योग की क्लास से ओम शब्द का उच्चारण ही हटा दिया था। योग के विरुद्ध घृणा का वायरस इंडोनेशिया, मिस्र जैसे देशों से मालदीव में आया, इसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

मालदीव में योग दिवस पर हुड़दंग करने वाले दर्जन भर से अधिक गिरफ्तार हो चुके हैं। उनमें पूर्व सांसद मोहम्मद इस्माइल भी है। पांच-छह ऐसे अभियुक्त हैं, जिन्हें माले पुलिस ने साठ दिनों के रिमांड पर भी लिया है। योग दिवस पर माले के गोलोल्हू स्थित नेशनल स्टेडियम में हमला करने की सारी साजिश क्या प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) ने रची थी? सरकार इसकी जांच में लगी हुई है। पीपीएम नेताओं ने बयान दिया है कि यह सब सत्तापक्ष का किया-कराया है। इतनी चाक-चौबंद सुरक्षा में पचास-साठ लोग झंडे और डंडे के साथ कैसे आयोजन स्थल के अंदर घुस सकते हैं?

इस प्रकरण में मालदीव के खेल मंत्री अहमद महलूफ का बयान महत्वपूर्ण है। महलूफ ने कहा, 'योग महोत्सव अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम के राष्ट्रपति रहते हुए भी होता रहा है। मगर, 21 जून, 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में हुड़दंग सोची-समझी साजिश का हिस्सा है, जिसमें पीपीएम और जमीयत सलाफ़ के लोग शामिल थे।' जमीयत सलाफ मालदीव में पब कल्चर, कैसिनो, नाइट क्लब, टैटू का प्रचंड विरोधी है। आगामी 1 जुलाई, 2022 को सरकार संसद में मालदीव को और सेक्युलर बनाने के वास्ते एक विधेयक लेकर आ रही है, जिसका विरोध जमीयत सलाफ़ के नेता अल शेख़ हसन मुसा फिकरे ने किया है। उन्होंने कहा, 'यह किस तरह का लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसमें टैटू बनाकर औरत मर्द हो जाए, और मर्द औरत? मालदीव में पब कल्चर व कैसिनो को मान्यता दिलाना है, और इस्लाम की मिट्टी पलीद करनी है।'

21 जून, 2022 के योग दिवस के दौरान जो विघ्न उपस्थित हुआ, क्या वह राजनीतिक व्यूह रचना का हिस्सा था? पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ही इसका बेहतर उत्तर दे सकते हैं। 2013 से 2018 तक अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति रहे। 2014 के बाद से माले में हर वर्ष योग दिवस आयोजित होता रहा है। जो लोग पकड़े गये हैं, उनमें पीपीएम के नेता अधिक हैं। निशाल अल शेख़, फज़लून बिन मोहमेद, मोहम्मद इस्माइल (पूर्व सांसद), मोहम्मद रज्जन जैसे नाम कई सारे सवाल खड़े करते हैं। मालदीव में इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने भी इस कांड की मज़म्मत की है।

23 सितंबर, 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सत्ता में आये थे। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के नेता सोलिह ने 17 नवंबर, 2018 को शपथ ली थी। संसदीय चुनाव वहां 2019 में हुआ था जिसमें इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को निचले सदन की 87 सीटों में से 65 सीटें हासिल हुई थीं। दूसरे-तीसरे नंबर पर जम्हूरी पार्टी और प्रोग्रेसिव पार्टी पांच-पांच सीटों के साथ संसद में हैं। पूर्व राष्ट्रपति और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) के नेता अब्दुल्ला यामीन दोबारा से सत्ता में आना चाहते हैं, वहां तक तो ठीक है, क्योंकि यह उस देश का अंदरूनी मामला है। मगर, मालदीव में सरकार विरोधी चक्रव्यूह में भारत को जिस तरह निशाने पर लिया जा रहा है, वह चिंता की बात है। गोलोल्हू नेशनल स्टेडियम में हमले की भर्त्सना कैबिनेट की बैठक में की गई। अटॉर्नी जनरल इब्राहिम रिफ़ात के साथ मालदीव का छह सदस्यीय मंत्री समूह पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहा है।

मालदीव दूतावास के कल्चरल सेंटर में योगाभ्यास 2012 से आयोजित होता रहा है। यहां योग शिक्षिका सविता हरीश बताती हैं कि काफी सारे स्थानीय लोग इस वास्ते संस्कृति केंद्र आते थे। लोकल टेलीविज़न भी योग क्लासेज़ कवर करता था। स्कूलों में योगासन की क्लास होती थीं। 13 से 15 फरवरी, 2016 में मालदीव-भारत के सहकार से 'हेल्थ एक्सपो' लगाया गया था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, विदेश मंत्री दुनिया मयमून, उस समय के भारतीय उच्चायुक्त अखिलेश मिश्रा ने पूरी सक्रियता दिखाई थी। कई सारे रिसॉर्ट वालों ने पर्यटकों के लिए योग की सुविधाएं दे रखी थीं। मालदीव डेमोक्रेसी नेटवर्क की कार्यकारी निदेशक शाहिंदा इस्माइल बताती हैं कि पीपीएम के नेता अब्दुल्ला यामीन जैसे ही सत्ता से बाहर हुए, इंडियन म्यूज़िक, डांस, योग, वेस्टर्न कल्चर सब कुछ से उन्हें एलर्जी हो गई।

पीपीएम के नेता अब्दुल्ला यामीन को लगा कि सत्ता में दोबारा से आना है, तो भारत की हर शै का विरोध करो। योग को हिंदू धर्म से जोड़कर मालदीव में राजनीतिक उन्माद पैदा करना भी इसी कवायद का हिस्सा रहा है। योग शिक्षिका सविता हरीश बताती हैं कि हमने यह सब देखकर योग की क्लास से ओम शब्द का उच्चारण ही हटा दिया था। योग के विरुद्ध घृणा का वायरस इंडोनेशिया, मिस्र जैसे देशों से मालदीव में आया, इसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज से तीस साल पहले 1992 में भारतीय दूतावास ने कैरो के इंडियन कल्चरल सेंटर में भारतीय भाषा, कला-संस्कृति और योग क्लासेज़ की शुरुआत की थी। उस कालखंड में अरब देशों के नौ स्पोर्ट्स चैनलों पर योग नमूदार होने लगा था। इससे खुंदक खाकर मिस्र के ग्रांड मुफ्ती अली गोमा ने 2004 में फतवा जारी किया कि इसे बंद करो, यह इस्लाम के विरुद्ध है।

उससे और पहले सिंगापुर में इस्लामिक रिलीजियस कौंसिल ने 1984 में फतवा जारी किया, 'गोकि योग करते समय मंत्रोच्चारण करते हैं, सूर्य नमस्कार जैसी उपासना है, यह सब इस्लाम के विरुद्ध है। इसे बंद किया जाए।' 22 से 24 अक्तूबर, 2008 को मलयेशिया के कोटा बारू में 83वीं नेशनल फतवा कौंसिल आहूत हुई, जिसमें योग को हराम घोषित किया गया था। इस पर वहां देशव्यापी बहस शुरू हुई, उसकी वजह योग का मलयेशियाई जीवन शैली में प्रवेश कर जाना था। औरतों से लेकर मलयेशियाई बच्चे तक योगाभ्यास करते थे। अचानक एक फतवे के ज़रिये पाबंदी सर्वस्वीकृत नहीं थी। 22 नवंबर, 2008 को स्टार ऑनलाइन टीवी पर एक प्रसारण के दौरान फतवा कौंसिल के चेयरमैन, डॉ. अब्दुल शकुर हुसैन ने कहा कि योग में तीन तत्व हैं- मंत्रोच्चार, शारीरिक मुद्रा और पूजा। केवल शारीरिक मुद्रा परिवर्तन से कोई दिक्क़त नहीं, मगर बाक़ी दो इस्लाम की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं।

किसी ज़माने में हिंदू व बौद्ध धर्म का बोलबाला था मालदीव में। वहां इस्लाम का प्रवेश 1147-48 ईस्वी में हुआ था। इस मुल्क में सुन्नी इस्लाम को अपनी ज़मीन तैयार करने में कई सौ साल लगे। 1990 में नव-सलाफी मूवमेंट की शुरुआत मालदीव में हुई, जिसने राजनीति को अपने हुजरे में समेट लिया। 2008 से पहले 'सुप्रीम कौंसिल फॉर इस्लामिक अफेयर्स' सत्ता के लिए 'खुल जा सिम-सिम' का काम करती थी। 2008 में ही इसका नाम बदलकर 'मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स' रख दिया गया। योग को लेकर पूर्वी एशियाई देशों में जो कुछ फतवेबाज़ी चल रही थी, स्वाभाविक है, मालदीव उससे बेअसर नहीं रहता। लेकिन यह भारत-मालदीव संबंधों के लिए सुखदायी नहीं है।

राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के मायने

नजरिया

दीपक कुमार त्यागी

चुनाव आयोग ने देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 जून है, देश के नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान 18 जुलाई को होना है और मतों की गिनती 21 जुलाई को होनी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़ा दांव चलते हुए झारखंड के राज्यपाल पद के दायित्व का लंबे समय तक सफलतापूर्वक निर्वहन करने वाली द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करवाकर विपक्षी दलों में जबरदस्त राजनीतिक भूचाल लाने कार्य किया है। ऐसा कर जहां देश को पहली बार आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति देने की तैयारी की गयी है, वहीं देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय व अनुसूचित जनजाति को साधते हुए, देश की महिला मतदाताओं को भी महिला सशक्तिकरण का संदेश देकर भाजपा के पक्ष में करने का प्रयास किया गया है। यह भी तय है कि भविष्य में द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा दिये गये सबका साथ सबका विकास' के नारे का देश में धरातल पर सबसे अहम व महत्वपूर्ण प्रतीक बनेंगी।

चुनाव आयोग ने देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 जून है, देश के नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान 18 जुलाई को होना है और मतों की गिनती 21 जुलाई को होनी है। जब से एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वे अचानक देश-दुनिया में फिर से चर्चाओं में आ गयी हैं,। आज लोग उनके निजी जीवन व राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून, 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के अन्तर्गत रायरंगपुर के बैदापोसी गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार हुआ था। द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम विरंची नारायण टुडू और माता का नाम किनगो टुडू है। वह अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हैं, उनका परिवार ओडिशा के एक आदिवासी जातीय समूह संथाल से ताल्लुक रखता है। बेहद पिछड़े और दूरदराज के जिले से ताल्लुक रखने वालीं मुर्मू ने गरीबी और अन्य समस्याओं से जूझते हुए वर्ष 1979 में आरबी वूमेंस कॉलेज, भुवनेश्वर से बी.ए. किया।

हालांकि उनका व्यक्तिगत जीवन बेहद कष्टकारी व त्रासदियों से भरा रहा है। उन्होंने अपने पति और दोनों बेटों को असमय खो दिया, अब उनकी सिर्फ एक बेटी इतिश्री है जिसकी शादी गणेश हेम्ब्रम से हो चुकी है। वैसे उनके पति स्वर्गीय श्यामचरण मुर्मू धालभूम स्थित यूको बैंक के प्रबंधक रह चुके हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के जीवन की सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उन्होंने जीवन पथ की दुश्वारियों से कभी हार नहीं मानी। विपरीत परिस्थितियों से लड़कर हमेशा बुलंद हौसलों के साथ जीवन पथ पर चलती रहीं। आज उनकी मेहनत व हिम्मत का सकारात्मक परिणाम सम्पूर्ण विश्व देख रहा है। द्रौपदी मुर्मू ने राजनीति में आने से पहले वर्ष 1979 से 1983 तक ओडिशा सरकार में सिंचाई व बिजली विभाग की जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1994 से 1997 तक श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च, रायरंगपुर में एक मानद सहायक शिक्षक के रूप में कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर की बात करें तो वह वर्ष 1996-1998 में रायरंगपुर नोटिफाईड एरिया काउंसिल से पार्षद बनकर काउंसिल की उपाध्यक्ष चुनी गयी थी। उन्होंने ओडिशा में दो बार भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा गठबंधन वाली नवीन पटनायक सरकार में 6 मार्च, 2000 से 6 अगस्त, 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में और 6 अगस्त, 2002 से 16 मई , 2004 तक मत्स्य पालन व पशु संसाधन विकास राज्यमंत्री के रूप में दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। संगठनात्मक स्तर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को पार्टी ने जब भी कोई छोटी या बड़ी जिम्मेदारी दी उन्होंने उसका पूरी ईमानदारी व मेहनत से निर्वहन किया। वह भाजपा में जिला स्तर से लेकर के पार्टी के एसटी मोर्चा में प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की पदाधिकारी रहीं। उनको वर्ष 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू ने 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक झारखण्ड के नौवें एवं प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

द्रौपदी मुर्मू के नाम राजनीति से जुड़ी विभिन्न राजनीतिक उपलब्धियां दर्ज हो गयी है, अब राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी के साथ नया इतिहास रचने की राह पर हैं। आज द्रौपदी मुर्मू देश की ऐसी शख्सियत बन गयी हैं जिन्होंने पार्षद से लेकर के देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने का सफर सफलतापूर्वक तय कर लिया है।

आजकल

भ्रष्टाचार का कठघरा

दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार के मामले में यहां के कुछ अफसरों के खिलाफ जैसी कार्रवाई की है, उससे एक बार फिर यह जाहिर हुआ है कि राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में कितनी बड़ी खाई हो सकती है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मातहत काम करने वाले तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में तैनात एक उप सचिव भी शामिल हैं, जिन पर एक पुराने मामले में कार्रवाई हुई है। इन अधिकारियों पर ताजा कार्रवाई का आधार यह है कि निलंबित अधिकारियों ने संपत्ति की खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी की थी। फिलहाल इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जाहिर है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी 'आप' की सरकार के लिए यह एक और बड़ा झटका है। यों दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपना पद संभालने के बाद यह साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी और इसके तहत जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्ती होगी। ताजा कार्रवाई को उनके इसी रुख का नतीजा माना जा सकता है। मगर अब इस मसले पर अगर फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव का नया अध्याय शुरू हो जाए, तो हैरानी नहीं होगी।गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के दो मंत्री पहले ही अलग-अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इनमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन धनशोधन मामले में इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं। दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है और इसमें सौ करोड़ रुपए हर्जाना मांगा है। यह स्थिति दिल्ली में पार्टी के नेताओं की है, जहां उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का एलान किया था और सिर्फ इसी वजह से उसके पक्ष में जनसमर्थन उभरा था।

इसके अलावा, हाल ही में पंजाब में 'आप' सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से इसलिए बर्खास्त कर दिया गया कि वे अपने महकमे में हर काम और निविदा के बदले एक फीसद कमीशन मांग रहे थे। विचित्र यह है कि पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद सिंगला ने भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता का दावा करते हुए कहा था कि किसी भी तरह के भ्रष्ट आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार के ही आरोपों के बाद उन्हें बर्खास्त और गिरफ्तार भी किया गया। आखिर आम आदमी पार्टी के सबसे मुख्य दावे में इतनी जल्दी इतना बड़ा फर्क आने की क्या वजह है! 'आप' की राजनीतिक बुनियाद ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के दावे पर ही तैयार हुई थी। इस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आम जनता के बीच यह वादा किया था कि वे देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति तैयार करेंगे, जो पूरी तरह भ्रष्टाचार से मुक्त होगी।

शिवसेना-संकट के सबक

राजनीति

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

यह मानकर चला जा सकता है कि महाराष्ट्र की गठबंधन-सरकार का सूर्य अस्त हो चुका है। यदि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने बाकी नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देने को भी तैयार हों तो भी यह गठबंधन की सरकार चलने वाली नहीं है, क्योंकि शिंदे उस नीति के बिल्कुल खिलाफ हैं, जो कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रति ठाकरे की रही है। शिवसेना के बागी विधायकों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि ठाकरे ने अपनी कुर्सी के खातिर कांग्रेस और एनसीपी को न सिर्फ महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंप दिए हैं बल्कि शिवसेना के विधायकों की वे ज़रा भी परवाह नहीं करते हैं। इसके अलावा ठाकरे के खिलाफ लगभग सभी शिवसेना के विधायकों की गंभीर शिकायत यह है कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों को भी मिलने का समय नहीं देते हैं। विधायक अपने निर्वाचकों की शिकायतें दूर करने के लिए आखिर किसके पास जाएं?

शिवसेना में बरसों से निष्ठापूर्वक सक्रिय नेताओं को इस बात पर भी नाराजगी है कि शिवसेना ने हिंदुत्ववादी भाजपा का साथ छोड़ दिया और जिस कांग्रेस के खिलाफ बालासाहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, उद्धव ठाकरे उसी की गोद में बैठ गए। उद्धव ने किसी वैचारिक मतभेद के कारण नहीं, बल्कि व्यक्तिगत राग-द्वेष और आरोपों-प्रत्यारोपों के कारण भाजपा से वर्षों पुराना संबंध तोड़ लिया। शिवसेना को वे एक राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं, बल्कि किसी सेना की तरह चलाते हैं। हर शिव सैनिक अपने कमांडर की हां में हां मिलाने के लिए मजबूर है। सेना से भी ज्यादा यह पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। जैसे बालासाहब की कुर्सी पर उद्धव जा जमे हैं, वैसे ही वे अपने बेटे आदित्य को अपनी कुर्सी पर जमाने के लिए उद्यत हैं। शिवसेना के अन्य नेताओं के मन में पल रही ये ही चिंगारियां आज ज्वाला के रूप में प्रकट हो रही हैं।

शिंदे के पास 2/3 बहुमत की बात सुनते ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री निवास छोड़ दिया है। वे ऐसे बयान दे रहे हैं, जैसे उन्हें मुख्यमंत्री पद की कोई परवाह नहीं है। वे कह रहे हैं कि सरकार रहे या जाए, शिवसेना के लाखों कार्यकर्त्ता उनके साथ हैं। लेकिन इस सरकार के गिरने के बाद शिवसेना के ये कार्यकर्ता पता नहीं किधर जाएंगे? वे शिंदे को अपना नेता मानेंगे या उद्धव ठाकरे को?

जाहिर है कि शिंदे अब कांग्रेस और शरद पवार से हाथ नहीं मिलाएंगे। उनकी गठबंधन सरकार अब भाजपा के साथ ही बनेगी। भाजपा उन्हें खुशी-खुशी उप-मुख्यमंत्री का पद देना चाहेगी। उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए शिंदे को भाजपा मुख्यमंत्री पद भी दे सकती है। यह घटनाक्रम देश के सभी नेताओं के लिए बड़ा सबक सिद्ध हो सकता है। एक तो राजनीतिक पार्टियों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी न बनने दिया जाए और दूसरा पदारूढ़ नेता लोग अहंकारग्रस्त न हों।